



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 अगस्त, 2006/1 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171004, 23 अगस्त, 2006

संख्या वि०स०-विधायन-गवर्न० बिल०/1-45/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य

परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 23-8-2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12)
का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ ।

(2) यह 27 मई, 2006 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उप-धारा (1) में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :- धारा 28 का
संशोधन ।

“परन्तु धारा 12 की उप-धारा (4) के अधीन आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की किसी अतिरिक्त रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन वर्ष की एक तिमाही के अवसान के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी द्वारा किया जा सकेगा और जहां निर्धारण प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि कर अवधि की विवरणियां सही और पूर्ण हैं, तो वह विहित रीति में ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय करेगा या आगामी कर अवधि के लिए उसका अग्रनयन अनुज्ञात करेगा :

परन्तु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी के विरुद्ध कोई अन्वेषण, संवीक्षा, निरीक्षण या लेखापरीक्षा या अन्य कोई जांच लम्बित है और प्रतिदाय मंजूर करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की यह राय है कि ऐसे प्रतिदाय के संदाय से ऐसे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो ऐसे अन्वेषण, संवीक्षा, निरीक्षण या लेखापरीक्षा या अन्य जांच की समाप्ति पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी से देय हो सकेगा, तो वह कारणों को लिखित में

अभिलिखित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी को प्रतिदत्त की जाने वाली रकम के बराबर की प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन, या तो अतिरिक्त आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की रकम का प्रतिदाय कर सकेगा या प्रतिदाय को कार्यवाहियों की समाप्ति तक रोक सकेगा :”।

2006 के
अध्यादेश
संख्यांक 2
का निरसन

3. (1) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

और
व्यावृत्तियां।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 28 के अन्तर्गत, आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की धारा 12 के अधीन अवधारित, किसी भी अधिक रकम का प्रतिदाय, प्रथम अप्रैल, 2005 से संगणित दो वर्ष की अवधि के पश्चात् ही किया जा सकता है। दो वर्ष की इस आरम्भिक वैधानिक अवधि की समाप्ति के पश्चात्, ऐसे प्रतिदायों के लिए पश्चात्वर्ती दावे प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के अन्त में किए जा सकते हैं। तथापि दो वर्ष के पश्चात् बहुत अधिक प्रतिदायों से बचने के लिए प्रतिदायों को नियन्त्रणीय (मैनिजेबल) और न्यूनतम सीमाओं में रखना अनिवार्य समझा गया। तदनुसार अधिक आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के प्रतिदायों के लिए विद्यमान समय-सीमा को संशोधित करने और जहां विवरणियां सही तथा पूर्ण हैं, वहां ऐसे प्रतिदायों के दावों को तिमाही आधार पर अनुज्ञात करने का विनिश्चय किया गया। ऐसे प्रतिदायों, जो राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डालें, से बचने के दृष्टिगत उन मामलों में जहां किसी भी व्यौहारी के विरुद्ध अन्वेषण या दूसरी जांचें प्रक्रिया में हों, प्रतिदायों को रोकने के लिए उपबन्ध करने का भी विनिश्चय किया गया।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में तुरन्त संशोधन किया जाना अपेक्षित था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (2006 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 2) तारीख 25 मई, 2006 को प्रख्यापित किया गया जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 27 मई, 2006 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मंत्री।

शिमला:

तारीख.....2006.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर वर्ष की एक तिमाही के अवसान पर आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अधिक रकम का प्रतिदाय प्राधिकृत करेंगे जिससे राजकोष से तिमाही प्रतिदाय अपरिहार्य हो जाएंगे जिनकी रकम का अग्रिम में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विधेयक के उपबन्ध, अधिनियमित होने पर वर्तमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं इसलिए कोई अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अधिक रकम का प्रतिदाय करने की रीति का उपबन्ध करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य एवं सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या ई0एक्स0एन0-एफ0(6)-7/2005]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2006 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2006

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2006.

Short title
and commence-
ment.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on 27th day of May, 2006.

2. In section 28 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, in sub-section (1), for the existing first proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

Amendment
of section 28.

“Provided that an application for refund of any excess amount of input tax credit under sub-section (4) of section 12, may be made by a registered dealer after the expiry of a quarter of the year and where the Assessing Authority finds that the returns for the tax period are correct and complete, it shall in the prescribed manner, refund to such registered dealer the excess amount of input tax credit or allow it to be carried forward to the next tax period:

Provided further that where any investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry is pending against the registered dealer, and the officer authorised to sanction the refund is of the opinion that the payment of such refund is likely to adversely affect the revenue which may become due from such registered dealer at the conclusion of such investigation, scrutiny, inspection or audit or other enquiry, he may, for the reasons to be recorded in writing, either refund the amount of excess input tax credit subject to furnishing of a security equal to the amount to be refunded to such registered dealer or withhold the refund till such time the proceedings are concluded.”.

3. (1) The Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2006 is hereby repealed.

Repeal of
Ordinance No.
2 of 2006 and
savings.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under section 28 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, refund of any excess amount of input tax credit determined under section 12 can be made only after expiry of two years reckoned from 1st April, 2005. After lapse of this initial statutory period of two years, subsequent claims for such refunds can be made at the end of each successive year. However, it is considered essential to keep the refunds within manageable and minimum limits to avoid huge refunds after two years. Accordingly, it was decided to amend the existing time-frame for refunds of excess input tax credit and permit claims of such refunds on quarterly basis in those cases where the returns are correct and complete. In order to guard against such refunds as might prejudicially affect recovery of revenue, it was also decided to provide for withholding of refunds in cases where investigations or other inquiries against any dealer are in process.

Since the Legislative Assembly was not in session and amendment of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 had to be made urgently, the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2006 (H.P. Ordinance No. 2 of 2006) was promulgated under Clause (1) of article 213 of the Constitution of India by the Governor of Himachal Pradesh on 25th May, 2006 which was published in the Rajpatra (Extraordinary) dt 27th May, 2006. Now, the said Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the said Ordinance without any modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The....., 2006.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill when enacted will authorise refund of excess amount of input tax credit after the expiry of a quarter of the year which will entail quarterly refund of money from the State exchequer, the amount whereof cannot be quantified in advance. The provisions of the Bill, after being enacted, are to be enforced through the existing Government machinery and no additional expenditure will be involved.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules providing for the manner of refund of excess amount of input tax credit. This delegation of power is essential and normal in character.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION
OF INDIA**

[Excise Deptt. FILE NO. EXN-F (6)-7/2005]

The Governor of Himachal Pradesh after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2006, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.

